

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई विस्ली, शुक्रवार, फरवर। 26, 1993/फारुगुन 7, 1914

No. 117]

NEW DELH!, FRIDAY, FEBRUARY 26, 1993/PHALGUNA 7, 1914

इ.स. भाग में भिम्म पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अक्ष्य संकलन के रूप में रखा जा सबसे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

विस महालय

(ग्रार्थिक कार्यविभाग)

(बैकिंग प्रभाग)

श्रादेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

न्त्रा 131(ग्र).—बैंककारी विनियमन ग्रधिनियम, 1949 (1949 新 10) 5 6 खण्ड (खा) केसाथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने उपधारा (1)सरकार रिजर्व बैक भारतीय केन्द्रीय बरसी ग्रावेदन पत्न पर विचार करने के बाद (जिसे लि, बरसी ग्र**हरी को**-श्रापरेटिव बैक कहा गया है) के सबध मे बैंक'' ''महकारी 26 फरवरी, 1993 को बैंक का कारोबार एनदुद्वारा

26 ग्रगस्त 1993 तक और ग्रिधिस्थगन को मिलाकर ग्रादेश करती हੈ, जिसके ग्रन्सार अधिस्थगन आदेश की श्रवधि के दौरान सहकारी बैक के विरुद्ध सभी कार्यवाइयो का शृष्ट किया जाना श्रथवा उमकी सभी कार्यवाइयो को जारी रखना स्थगित किया जाता किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के ग्रधिस्थगन का किसी ंभी प्रकार से महाराष्ट्र को-श्रापरेटिव सोसायटी ग्रधिनियम, प्रन्तर्गत 1960 के महाराष्ट्र द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उसके श्रधिकारी पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पडेगा।

2 केन्द्रीय सरकार एतदहारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत ग्रिश्वस्थगन की ग्रवित्र के दौरान यह सरकारी बैक भारतीय रिजर्व वैक की लिखित पूर्वानुमानित के बिना कोई ऋण श्रथवा ग्रिंगिम नही देगा किमी ग्रिग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा बैंक की किमी परि- सम्पत्ति का ग्रन्थ संक्रामण ग्रथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का वायित्व स्वीकार नहीं करेगा कोई निवेण नहीं करेगा ग्रथवा ग्रपने दायित्व और देन-दारियों के संबंध में ग्रथवा ग्रन्थया किसी प्रकार की ग्रदायगी नहीं करेगा ग्रथवा ग्रदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा श्रथवा ग्रदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझोता अथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्न-लिखित सीमा तक यथास्थिति ग्रदायगियां ग्रथवा खर्च करेगा:—

(1) प्रत्येक बचत बैंक ग्रथवा चाल् खाते ग्रथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी ग्रन्थ जमा खाते में शेप रकम में से 100 रु तक:--

बणर्ते कि श्रदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी श्रग्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राणि के 100 रुपए से ज्यादा नहीं:

यह भी भर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम ग्रदानहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी वैंक का कर्जदार हो,

- (2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट भुगतान ध्रार्डर अथवा चैंकों की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा घ्रिध-स्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है;
- (3) 26 फरवरी, 1993 को भ्रथवा उसमे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राणि चाहे वे उस तारीख से पहले उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हों;
- (4) ऐसा कोई ध्यय जो महकारी बैंक के द्वारा भ्रथवा उसके विरूद्ध दायर किए गए मुकदमे, ग्रपील भ्रथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरूद्ध ली गयी डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना श्रावश्यक हो;

बंशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, ग्रंपील ग्रंथवा डिकी के संबंध में किए जाने वाले व्ययं की रकम यदि 500 रुपये से श्रधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित श्रनुमित ली जाएगी :

- (5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमीयम की राशि हो;
- (6) किसी ध्रन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना ध्रनिवार्य हो;

बगर्ते कि जहां किसी एक कैलैण्डर मास में किसी मद परिकया गया कुल खर्च श्रधिस्थगन श्रादेण से पहले के छ: महीनों में उस मध पर किए गए मासिक व्यय से वर उस श्रवधि के दौरान जहां उम मद किया गया हो और उस पर कोई व्यय नहीं प्रकार किया जाने वाला व्यय 250 रुपए जाए तो उस प्रकार का व्यय करने मे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप मे ग्रन्मित ली जाएगी।

- 3. केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत श्रधिस्थगन की ग्रवधि के दौरान :--
 - (क) यह महकारी बैंक निम्नलिखित और श्रदायगियां कर सकेगा, श्रर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों
 श्रथवा श्रन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र
 मरकार, श्रथवा महाराष्ट्र स्टेट को-श्रापरेटिव
 बैंक लि या शोलापुर जिला केन्द्रीय सहकारी
 बैंक लि. श्रथवा भारतीय स्टेट बैंक
 श्रथवा इसके किन्ही सहायक बैंकों या
 किसी श्रन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को
 दिए गए ऋण ग्रथवा श्रग्निमों जो श्रधिस्थगन
 श्रादेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए
 जाने शेष थे, की वापसी श्रदायगी के लिए
 श्रावश्यक हों।
 - (ख) सहकारी बैंक को पूर्वांक्त श्रदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोश्रापरेटिय बैंक लि. श्रथवा किसी श्रन्य बैंक के साथ श्रपने खाते चलाने की श्रनुमित दी जाएगी परन्तु इस श्रादेश का ऐसा कोई श्राणय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-श्रापरेटिय बैंक लि. श्रथवा वैसे किसी श्रन्य बैंक को इस संबंध में श्रपने श्रापको श्राक्ष्यस्त करना होगा कि इस श्रादेश द्वारा लगाई गयी शतों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।
 - (ग) यह सहकारी बैंक उन हुंडियों को जो वसूल न कीं गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के प्रनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई प्रधिकार प्रथवा हक न हो ग्रथवा बैसी हुंडियों में उसका कोई हित नहो।
- (घ) सहकारी बैंक ऐसे माल ग्रथवा प्रतिभूतियों को जोइस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकव, कर्ज ग्रथवा ग्रोवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक ग्रथवा

क्षधक रखी गयी हा, अथवा अन्यया प्रभारित की गयी हो, निम्निलिखित मामलो मेछोड अथवा देमकेगा —

- (1) किसी ऐसे मामले मे जहा यथास्थिति ऋण-कर्ताग्रा से मिलने वाली मारी कम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है ग्रीर
- (2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा समय हो, निर्दिष्ट अनुपातो में नीचे अथवा उन अनुपातो से नीचे, जो अधीनस्थ आदेश के प्रभावी होने में पहले लागू थी, इनमें जा भी अधिक हा, उक्त माल और प्रतिभूतियो पर मार्जिन के अनुपातो का कम किये बिना।

[स 10(1)/93-विकास] पी के तेजयान, श्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

- SO 131(E)—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 45, read with clause (7b) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Barsi Central Urban Co-operative Bank Ltd, Barsi (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th February 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960
- 2 The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advan-, alienate or dispose of any assets of the bank incur any liability, make any investment or make oi agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arranagement, except making of payments, oi incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder—
 - (i) Out of the balance in every savings bank or current occount or in any other deposit account by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100
 - Provided that the sum of the amount paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs 100
 - Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co operative Bank in any way
 - (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unipaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

- (iii) the aamount of bills received for collection on or before the 26th February 1993 whether realised before, on or after that date,
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incuried in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co operative Bank, or for realising any amounts due to it,
- Provided trat if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred,
- (v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day to day administration of the Co-operative Bank,
- Provided that where the total expenditure on any item in any calender month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs 250/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred
- 3 The Central Government hereby also directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank
 - (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Cooperative Bank Ltd or Solapur District Central Co-operative Bank Ltd or the State Bank, of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining uppaid on the date on which the order of moratorium comes into force,
 - (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-coperative Bank Itd, or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid:
 - Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra. State Co-operative Bank I to of such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank,
 - (c) may return any bills which has remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co operative Bank has no right or title so, or interest in such bills,
 - (d) may release of deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borroweis, as the case may be has been received by the Co operative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the pro-

portions of the margins on the said goods or secunities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher

[F No 10(1)|93 Dev]
P K TEJYAN, Under Secy

ग्रादेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का थ्रा. 132(थ्र) --वैककारी विनियमन श्रधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त गक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये भ्रावेदन पत्न पर विचार करने के बाद पंजाब को-ग्रापरेटिव ग्रर्बन बैंक लि , पुणे (जिसे इसके पश्चात् ''सहकारी बैंक '' कहा गया है) के सबध मे एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर, 26 श्रगस्त, 1993 तक श्रौर उस दिन को मिलाकर भ्रधिस्थगन म्रादेश जारी करती है, जिसके श्रनुसार श्रधिस्थगन श्रादेश की ग्रवधि केदौरान सहकारी बैक के विरुद्ध सभो कार्रवाइया का गुरू किया जाना श्रयवा इसकी सभी कार्यवायियो को जारी रखनास्थगित किया जाता है किन्तु मर्तयह है कि इस प्रकार के श्रधि-स्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-ग्राप^{रे}टिव के भ्रन्तर्गत महाराष्ट्र सोसाइटी ब्रधिनियम, 1960 सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाते वाले उसके अधिकारी पर प्रतिकुल प्रभाव नही पडेगा।

- 2 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत प्रिधिस्थान की प्रयधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्ब बैंक की लिखित पूर्वानुमित के बिना कोई ऋण प्रथवा प्रिप्तम नहीं देगा, किसी प्रिप्तम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक को किसी परिमम्पिन का ग्रन्य सकामण प्रथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का द्यायत्व स्वीकार नहीं करेगा कोई निवेश नहीं करेगा ग्रथवा ग्रन्था किसी प्रकार की प्रदायगी नेहीं करेगा प्रथवा ग्रन्था किसी प्रकार की प्रदायगी नहीं करेगा प्रथवा ग्रन्था करना स्वीकार नहीं करेगा प्रथवा ग्रन्था करना स्वीकार नहीं करेगा प्रथवा ग्रन्था करना समझौता ग्रथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलाखित तरीके से ग्रीर निम्नलाखित सोमा तक यथास्थित ग्रदायगिया ग्रथवा खर्च करेगा
- (1) प्रत्येक अचत बैंक प्रथवा चालू खाते प्रथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी प्रत्य जमा खाते में शेष रकम भे से 100 रुपये तक

बशर्ते कि ग्रवा की गयी रकम की कुल मीमा किसी एक व्यक्ति (किसी श्रन्य व्यक्ति के साथ मयुक्त खाते मे नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राणि के 100 रुपये से ज्यादा न हों, यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम श्रदा नहीं की जायेगी जो निसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

- (2) ऐसे किसी बैंक ड्रापट, भुगतान श्रार्डर ग्रथवा चेका की राशि, जो सहकारी बैंक द्वारा श्रिधस्थगन ग्रादण के लागू होने की नारीख से पहले जारी कर दिये गये थे श्रीर जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है,
- (3) 26 फरवरी, 1993 को श्रथवा उससे पूर्व भुगतान के लिये प्राप्त हुडियो की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख का या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हो,
- (4) ऐसा काई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा श्रथवा उसके विरुद्ध दायर किये गये मुकदम, श्रपील श्रथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गयी डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना श्रावश्यक हो,

बणर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, श्रपील श्रथवा डिक्री के सबध में किये जाने वाले व्यय की रकम यदि 500 रुपये में श्रधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित श्रनुमित ली जायेगी

- (5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बोमा श्रौर प्रत्यय गारटी निगम को देथ प्रीमियम की राशि हो, श्रौर
- (6) किसी ग्रन्थ सद पर कोई व्यय, जहा तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार मे बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिये करना भ्रनिवार्य हो

बशर्ते कि जहां किसी एक कैलैंडर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थागन आदेश से पहले के छ कैलैंण्डर महीनों में उस मद पर किये गये श्रीसत मासिक प्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो श्रीर उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250-रुपये से बढ़ जाये तो उस प्रकार का प्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में प्रनुमित ली जायेगी।

- 3 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीकृत श्रिधस्थगन की ग्रविध के दौरान —
 - (क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित ग्रौर ग्रदायगिया कर सकेगा श्रथीत् सरकारी प्रतिभूतियो ग्रथवा ग्रन्थ प्रतिभूतियो के बदले महाराष्ट्र सरकार, ग्रथवा महाराष्ट्र स्टेट को-ग्रापरेटिव बैंक लि या पुणे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि श्रथवा भारतीय स्टेट बैंक ग्रथवा इसके किन्ही सहायक बैंको या किसी ग्रन्य बैंक द्वारा

सहकारो बैंक को दिये गये ऋगों श्रयका ग्रिग्रमों जो श्रधिस्थगन ग्रादेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाये जाने गेप थे की बापसी श्रदायगी के लिये ग्रावश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंकों को पूर्वोक्त ग्रदायगियां करने के लिये महाराष्ट्र स्टेट को-म्रापरेटिव बैंक लि. ग्रथवा किसी ग्रन्य बैंक के साथ ग्रपने खाते लाने की ग्रनुमति दी जायेगी।

परन्तु इस म्रादेश का ऐसा कोई भ्राणय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के लिये दिये जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-म्रापरेटिव बैंक लि. श्रथवा वैसे किसी भ्रन्य बैंक को इस संबंध में भ्रपने ग्रापको ग्राप्यस्त करना होगा कि इस ग्रादेण बारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

- (ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हो, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के श्रनुरोध पर लौटा सनेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियो पर कोई ग्रिधकार श्रथवा हक नहो श्रथवा वैसी हुंडियो में उसका कोई हिंत नहो।
- (घ) महकारी बैंक ऐसे माल ग्रयवा प्रतिभूतियों, को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण नकद कर्ज ग्रयवा ओवरड़ाफ्ट के बदले गिरवी, वृष्टि-बंधक ग्रथवा बंधक रखी गयी हो ग्रथवा ग्रन्थया प्रभारित की गयी हो, निम्न शिखित मामलों में छोड़ ग्रथवा देकि ---
- (1) किसी ऐसे मामलेमें जहां यथास्थिति ऋणकर्ताओं मे मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैक द्वारा बिना मर्त प्राप्त की गई हैं; और
- (2) किसी अन्य मामले में, उस मीमा तक की रकम जितनी अप्रवश्यक अथवा संभव हो, निदिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अभुपातों से नीचे, जो अधिस्थान आवेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी अधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर माजिन के अनुपातों को कम किये बिना।

[सं. 10(2)/93-विकास] पी.कं. तेजयान, भ्रवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S.O. 132(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 45, read with clause (2b) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application midde by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect

of the Punjab Co-op. Urban Bank Ltd., Pune 411 002 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th February 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

- 2. The Central Government hereby directs that, during the period of moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance alienate or dispose of any assets of the bank, incure any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments or incurring of expenditure, as the case may be to the extent and in the manner provided hereunder:—
 - (i) Out of the balance in every savings bank or current account or any other deposit account, by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100/-.

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100/-.

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way:

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes in to force;
- (18) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February, 1993 whether realized before on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Cooperative Bank, or for realizing any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- (v) the amounts of premium payable to Deposit insurance and Credit Guarantee Corporation; and.
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank secessary for carrying on the day-to-day administration of the Cooperative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250/, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- 3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the co-operative bank---
 - (a) may make the following further payments, namely the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or Pune District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtia State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Cooperative Bank has no right or title to, or interest in such bills;
- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—
- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(2)/93-Dev] P. K. TEJYAN, Under Secy.

ग्रादेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का. भा. 133 (भ्र):-बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ख) केसाथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा दिये पक्ष पर विचार करने गये आवेदन के बाद सहकारी लि., बम्बई 400013 जिसे सहकारी बैक पश्चात् कहा गया इसके में एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 को बैक का कारों-बार बंद होने से लेकर 26 ग्रगस्त, 1993 तक को मिलाकर अधिस्थगन म्रादेश करती जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभीकार्यवाइयों का शरू किया जाना प्रथमा गुरू की गई कार्यवादयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को श्रापरेटिन सोसाइटी अधिनियम 1960 पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निवेण देती है कि स्वीकृति श्रीधस्थगन की अविध के दौरान यह सह-कारी बैंक भारतीय रिजर्ब बैंक की लिखित पूर्वानुमित के बिना कोई ऋण अथवा श्रीग्रम नहीं देगा किसी

का नवीकरण नहीं करेगाबैक की किसी परि-सम्पत्ति का अन्य निबटान नहीं करेगा संकामण अथवा दायरिव करेगा।कोई निवेश नहीं करेगा श्रथवा अपने दायित्वों और देनदारियो क संबंध में भ्रथवा अन्यया किसी प्रकार के श्रदायनी नहीं करेगा श्रथवा श्रदायनी स्वीकार नहीं करेगा प्रथया किसी प्रकार का समझौता ठहराव नहीं करेगा किन्त् यह निम्नलिखित से भ्रौर निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अथवाखर्चकरेगाः~~ अदागयी

- (1) प्रत्येक बना बैंक ग्रथना चालू खाते किसी भी नाम से पुकारे जाने नाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100/ रुपये तक:---
- बशर्ते कि श्रदा की गयी रकम की कुल सीमा किसी एक ट्यांक्त (किमी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम डे खाते में जमा कुल राशि के 100/- इनये में ज्यादा न हों:
- यह भी गर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम ग्रदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,
 - (2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर अयवा चैकों की राशि, जो सहकारी बैंक अधिस्थगन आदेश के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गएथे और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है,
 - (3) 26 फरवरी, 1993 को श्रयवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हो
- (4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा प्रथवा क्सक विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें, ग्रंपील प्रथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गई डिकी या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना श्रावण्यक हो,

बशर्ते कि प्रत्येक मुकदमें, श्रपील श्रथवा डिक्री के संबंध में किये जाने वाले व्यय की रकम यदि 500/- रुपये से श्रधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखिन श्रनुमित ली जायेगी:

(5) ऐसा कोई ब्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमियम की राशि हो, और (6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बक के विचार में बैक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिये करना ग्रनिवार्य हो.

बणरों कि जहां किसी एँक कलैण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च ग्रिधिस्थगन श्रादेण संपहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किये गये औसत मासिक घ्यम से बढ़ जाता हो, श्राय वा उस श्रविधि रे दौरान जहा उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/-रुपये से बढ़ जाये तो उस प्रकार का व्यय करने में पूर्व भारतीय रिजर्ब बैंक की लिखित रूप में श्रनुमित ली जायेगी।

- 3. केन्द्रीय सरकार एतदृद्रारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक स्वीष्टत ग्राधस्थगन की ग्रवधि के दौरान .--
 - (क) यह सरकारी बैंक निम्निलिखन और प्रवायगियां कर संकारा, अर्थान् सरकारी प्रतिभृतियों प्रथवा अन्य प्रतिभृतियों प्रथवा अन्य प्रतिभृतियों के बढले महाराष्ट्र सरकार, प्रथवा महाराष्ट्र स्टेट को आपरेटिय बैंक लि. या मुम्बई जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि अथवा भारतीय स्टेट बैंक प्रथवा इसके किन्हीं सहायक बैंको या किसी अन्य बैंक टारा सहकारी बक को विथे गये ऋणो अथवा अग्निमों, जो अधिम्धगन आवेश के प्रभावी होने की नारीख़ को चुकाये जाने शेष थे, की बापसी अदायगी के लिये आवश्यक हो।
 - (ख) सहकारी बैंक को प्योंकत ग्रदायिगया करने स्टेट को-ग्रापरेटिव के लिये महाराष्ट्र लि. भ्रयवा किसी भ्रन्य बैंक देत्साथ ग्रपने खाते चलाने की श्रनुमानि दी जायेगी । परन्त् इस ग्रादेश का ऐसा कोई ग्रागय नही होगा कि इस सहकारी बैक को किसी रक्तम के दिये जाने से पहले महाराष्ट्र ग्रापरेटिय बैक लि. ग्रथवा जैसे किसी श्रन्य बैक को इस संबंध में ग्राप्ते ग्रापको ग्राप्यस्त करना होगा किइस श्रादेश द्वारा गयी भती का इस बंक द्वारा पालन किया जा रहा है।
 - (ग) यह सहकारी बैंक उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के धनुरोध पर लौटा सक्षेगा। यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई प्रधिकार प्रथवा हक नहीं प्रथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हित न हों।
 - (घ) सहकारी बैंक ऐसे माल भ्रथवा प्रतिभृतियों को जो इस (बैंक) वेंग्यास किसी ऋण

- नकद, कर्ज अथवा श्रोबरङ्गिट के बदले गिरवी दृष्टि-बंधक श्रथवा बंधक रखी गयी हों, श्रथवा श्रन्यथा प्रभारित की गयी हो, निम्नलिखित मामलों में छोड़ श्रथवा दे सनेगा:——
- (1) किसी ऐसे मामले में जहां, यथास्थिति ऋण-कर्ता या ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है और
- (2) किसी प्रत्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी ग्रावक्यक प्रथवा संभव हो, निदिष्ट ग्रतुपातों से नीचे ग्रथवा उन प्रतुपातों से नीचे, जो ग्राधिस्थगन ग्रादेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी ग्राधिक हों, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के ग्रनुपातों को कम किये बिना।

[फा.सं. 10(3)/93-विकास] पी.के. नेजयान, भ्रवर सिचव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

- S.O. 133(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 45, read with clause (2b) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Kolhapur Sahakari Bank Ltd., Bombay-400013 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th February, 1993 upto and inclusive of the 26th August, 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtia of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.
- 2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance alienate or disposed of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be to the extent and in the manner provided hereunder:—
 - (i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit, account by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100|-:
 - Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100/-;
 - Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;
 - (ii) The amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
 - (iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February, 1993 whether realized before, on or after that date;

- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Cooperative Bank, or for realizing any amounts due to it;
- Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.
- (v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure or any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to day administration of the Co-operative Bank:

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- 3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank—
 - (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or Mumbal District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
 - (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making tse payments aforesaid:
 - Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;
 - (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;
 - (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borτower or borrowers, as the case may be, has been received by the Cooperative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium, came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(3)/93-Dev.] P. K. TEJYAN, Under Secy.

ग्रादेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का. ब्रा. 134(म्र):-बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यज) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के भन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विए गए ग्रावेदन-पत्र पर विचार करने के बाद धुले पिपल्स को-ग्रापरेटिव बैंक लि., धुले (जिमे इसके पश्चात ''सहकारी बैंक" कहा गया है) के संबंध में, एतद्द्वारा 26 फरवरी, 1993 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 26 अगस्त, 1993 तक और उस दिन को मिलाकर स्रधिस्थगन स्रादेश जारी करती है, जिसके श्रनुसार ग्रधिस्थगन भ्रादेश की भ्रविध के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गई कार्रवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के श्रधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-म्रापरेटिव सोसाइटी मधिनियम, 1960 के मन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके ग्रधिकारों पर प्रतिकृल प्रभावनहीं पद्देगा ।

- 2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत प्रधिस्थगन की भ्रविध के दौरान यह पहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमित के बिना कोई ऋण प्रथवा भ्रप्रिम नहीं वेगा, किसी भ्रप्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का ग्रन्य संक्रामण प्रथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का वायित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा श्रथवा भ्रपने दायित्वों और वेनदारियों के संबंध में अथवा भ्रन्यथा किसी प्रकार की भ्रदायगी नहीं करेगा भ्रथवा भ्रयवा भ्रदायगी नहीं करेगा भ्रथवा भ्रवायगी करना स्वीकार नहीं करेगा भ्रथवा किसी प्रकार की भ्रदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा भ्रथवा किसी प्रकार का समझौता भ्रथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति श्रदायगियां भ्रथवा खर्च करेगा:——
 - (1) प्रत्येक बचत बैंक श्रथवा चालू खाते श्रथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी श्रन्य जमा खाते में शेष रकम में से 100/- रुग्ए तक.---

बगर्ते कि श्रदाकी गयी रकम की कुल सीमा किसी एक व्यक्ति (किसी श्रन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि के 100/- रुपए से ज्यादा न हो:

यहं भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम ग्रदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान श्रार्श्वर भ्रथवा चेकों, की रागि, जो सहकारी बैंक द्वारा प्रधिस्थगन म्रादेश के लागू होने की तारीख मे पहले जारी कर दिए गए थे, और जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया ;

- (3) 26 फरवरी, 1993 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीख से पहले उस तारीख को या उस तारीख के बाद वमुल की गयी हों;
- (4) ऐसा कोई व्यय जो सहकारी बैंक के द्वारा श्रथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे, श्रपील श्रथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी डिकी या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध मे करना श्रावश्यक हो,

बणतें कि प्रत्येक मुकदमें, श्रपील ग्रथव¹ डिकी के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम यदि 500/- रुपए से श्रधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित ग्रन,मिल ली जाएगी,

- (5) ऐसाकोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमयम की राणि हो, और
- (6) किसी प्रत्य मद परकोई ब्यय, जहां तक कि वह व्यय महकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रणासन चलाने के लिए करना प्रनिवार्य हो:

बणतें कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्च प्रिधिस्थगन याउँण से पहले के छ: कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किए गए औसन मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, अथवा उस अविध के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250/- रुपए से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी ।

- केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि महकारी बैंक स्वीकृत प्रधिस्थगन की श्रविध के दौरान ---
 - (क) यह सरकारी बक निम्नलिखित और श्रदायगिय(कर सकेगा, अर्थात् सरकारी प्रतिभृतियों श्रयं श्रयं श्रयं प्रतिभृतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-श्रापरेटिव बैंक लि. या धुले जिला केन्द्रीय महकारी बैंक लि. श्रयंवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किन्हीं महायक बैंको या किसी अन्य बैंक द्वारा महकारी बैंक को दिए गए ऋणों श्रयंवा अग्निमो, जो श्रिधस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को चुकाए जाने शेप थे, की वापसी अदायंगी के लिए आवश्यंक हो।
 - (ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगिया करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट-को-आपरेटिव बैंक लि. अथवा किसी

अन्य बैंक के साथ श्रपने खाने चलाने की श्रनुमति दी जाएगी ।

परन्तु इस म्रादेश का ऐसा कोई म्राशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-म्रापरेटिय बैक लि. म्रथया वैसे किसी म्रन्य बैक को इस संबंध में म्रपने म्रापको म्राश्वस्त करना होगा कि इस म्रादेश द्वारा लगाई गयी शर्ती का इस बैंक बारा पालन किया जा रहा है।

- (ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियों को, जो बसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के प्रनुरोध पर लौटा मकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई ग्रधिकार प्रथवा हक न हों ग्रथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हिला न हों।
- (घ) सहकारी बैंक ऐसे माल प्रथवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक श्रथवा बंधक रखी गयी हों, श्रथवा श्रन्यथा प्रभारित की गयी हों, निम्नलिखित मामलों में छोड़ श्रथवा दे सकेगा :---
 - (1) किसी ऐसे मामले में जहां, यथास्थिति ऋणकर्ता या ऋणकर्ताओं से मलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना गर्त प्राप्त की गई है; और
 - (2) किसी आय मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातो से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू भी, इनमे जो भी अधिक हो, उबत माल और प्रतिभृतियों पर माजिन के अनुपातों को कम किए विना।

[फा. सं. 10(4)/93—विकास] पी. के. तेजयान, ग्रवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

S.O. 134(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 45, read with clause (2b) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (i) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Dhule People's Co-operative Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (hereinafter referred to as th Co-operative Bank), or the period fom close of business on the 26th February 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in

any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

- 2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank incur any hability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangements, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder:—
 - (i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called a sum not exceeding Rs. 100;
 - Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100;
 - Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;
 - (i1) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
 - (iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February, 1993 whether realized before, on or after that date;
 - (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Cooperative Bank, or for realizing any amounts due to it:
 - Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;
 - (v' the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
 - (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the tlay-to-day administration of the Co-operative Bank;
 - Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar month preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.
- 3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank—
 - (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operativt Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Dhule District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
 - (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on the request being made in this behalf by such persons if the Co-operative Bank has no right or title to or interest in such bills;
- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or other-wise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent,—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions, of the margins on the said goods on securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(4)/93-Dev] P. K. TEJYAN, Under Secy.

श्रादेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

का. श्रा. 135 (स्र):--बैंककारी विनियमन प्रधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 वे खण्ड (यखा) के साथ पठित भारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदेत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए भ्रावेदन-पत्न पर विचार करने के बाद स्वास्तिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बम्बई-400002 (जिसे इसके पण्चात ''सहकारी बैंक'' कहा गया है) के संबंध में एतदद्वारा 26 फरवरी, 1993 बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर 26 ग्रगस्त, 1993 तक और उस दिन को मिलाकर ग्रधि-स्थगन श्रादेश जारी करती है, जिसके धनुसार प्रधिस्यगन श्रादेश की श्रवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों का शरू किया जाना श्रथवा इसकी सभी कार्रवाईयों को जारी रखना स्थिगित किया जाता है किन्तू मर्त यह है कि इस प्रकार के श्रधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-श्रापरेटिव सोसाइटी श्रधिनियम, 1960 के अंतर्गत माराष्ट सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके श्रधिकारी पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार एनत् द्वारा यह निदेश देती है कि स्वीकृत अधिस्थान की श्रवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमित के बिना कोई ऋण श्रयवा श्रप्रिम नहीं देगा, किसी श्रप्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक को किसी परिसम्पत्ति का अन्य संकामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का द्वाधित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा श्रयवा श्रपन द्वाधित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई

संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की श्रदायगी नहीं करेगा अथवा श्रदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्निपिधिन तरीके से और निम्निष्धित सीमा तक यथा-रिथित श्रदायगियां अथवा खर्च करेगा :—

(1) प्रत्येक अचन बैक अथवा पालू खाते अथवा किसी भी नाम ने पुकारे पाने वाले किसी अन्य जमा पाते ने शेष किस में भे 100/- छपए तक :--

> ब्रशनें कि झदा का गयी रकम की कुल नीमा निगी एक व्यक्ति (जिमी अन्य व्यक्ति की माथ मंयुक्त खाते में नहीं) के नाम में खाने में जना जुल राशि के 100/- रपण के ज्यादा न ही:

> यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम - श्रदा नहीं की आएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

- (१) ऐसं किसी बैंक ड्राफ्ट, भगतान घ्रार्डर श्रथवा नेकों की राणि, जो सहकारी बैंक हारा प्रधिस्थगन बादिण के लागू होने की तारीख से पहले जारी कर दिए गए थे और जिनका उस तारीख तक भगतान नहीं किया गया,
- (3) 26 फरवरीं, 1903 की श्रयवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुँडियों की श्रांत खाहे के उस तारीख में पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की सपी हो,
- (4) ऐसा कोई व्यय जो महकारी बैंक के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए म्कदमें, अपोल अथवा महकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी डिकी या बैंक की मिलने वाली किसी रकम को बसूल करने के संबंध में करना अविषयक हो :

बगर्तो कि प्रत्येक मुक्तदमें भ्रमील श्रथवा डिक्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रक्तम याद 500/- रुपए से श्रधिक हो, तो खर्च करने में पहले भारतीय रिजर्ब बैंक की लिखित श्रमुमति ली जाएगी,

- (5) ऐसा कोई ब्यय जो निक्षेप वीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देय प्रीमियम की राणि हो; और
- (6) किसी श्रन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैक के विचार में बैक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो :

वशर्ते कि जहां किसी एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खर्चे श्रधिस्थान श्रादेश से पहले के छः कैलेण्डर महोनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो, श्रयवा उस श्रवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने बाला व्यय 250/- रुपए से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्ब बैंक की लिखित का में अनुमति ली जाएकी ।

- केन्द्रीत सरकार एनय्द्रारा यह भी निदेश देनी है कि सहवारी बैठ स्वीकृत प्रक्षिस्थमन की अवधि के बोलान---
 - (क) यन सहकारी जैक निम्नलिखित और श्रदासिया कर सकेता, अर्थान् सरागरी प्रतिन्तियो अयवा अन्य प्रतिन्तियों के बदले महाराष्ट्र सरकार, अयवा महाराष्ट्र सरकार, अयवा महाराष्ट्र सरेट को-आपरेटिव बैक लि. या गृबई जिला केन्द्रीय महनारी बैक लि. प्रथया भारतीय स्टेट बैक अथवा इसके किन्ही महायक बैकों या किसी अन्य बैक हारा सहकारी बैक को दिए गए, ऋणो श्रयवा श्रिप्रमों, जो श्रधिस्थान अपेया के प्रभावी होने की तारीण को चुकाए जाने लेप थे, की वापनी श्रदायर्ग के लिए श्रावश्यक हो ।
 - (ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त ग्रदायशियां करने के लिए महाराप्ट्र स्टेंट को-श्रापरेटिव बैंक लि. श्रथवा किसी श्रन्य बैंक के साथ श्रपने खाते चलाने की श्रदुर्भात दी जाएगी ।

परन्तु इस श्रादेश का ऐसा कोई ग्राणय नहीं होता कि इस सहकारी बैक को किसी रकम के श्रिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिब बैक लि. अथवा वैसे किसी श्रस्य बैंक को इस संबंध में अपने अपने श्राण्यण करना होगा कि इस श्रादेश हारा लगाई गयी भतीं का इस बैंक हारा पालन किया जा रहा है।

- (ग) यह महकारी बैक, उन हुं छियो को, जो बसूल न की गर्या हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैक का उन हु छियो पर कोई आधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी हुं छियों में उसका कोई हित न हो।
- (घ) सहकारी बैंक ऐसे माल श्रयवा प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकद, कर्ज श्रयवा ओवरड़ापट के बदले गिरवी, दृष्टि-बंधक श्रयवा बंधक रखी गयी हों, श्रयवा श्रन्यथा प्रभारित की गयी हों, निम्नलिखित मामलों में छोड श्रयवा देसकेंगः—
 - (1) किसी ऐसे मामने में जहां यथास्थिति ऋण-कर्ताओं में मिलने वाली मारी रकम सहकारी बैक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गई है; और
 - (॰) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी श्रावश्यक श्रायदा संभव हो,

निर्विष्ट प्रमुपातों से तीचे प्रथवा उन प्रमु-पातों से नीचे जो प्रधिस्थान प्रादेश के प्रभावी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भी प्रधिक हो, उक्त माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के प्रमुपातों को कम किए बिना।

> [फा. सं. 10(5)/93-विकास] पी. के. तेंजयान, ग्रवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1993

- S.O. 135(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 45, read with clause (2b) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of Indra under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Swastik Innata Sahakari Bank Ltd., Bombay-400 002 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 26th Feb. 1993 upto and inclusive of the 26th August 1993 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.
- 2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance alienate or dispose of any assets to the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder:—
- (i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 100;

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 100:

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-opcative Bank and remaining unpaid on the date on whih the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before 26th February 1993 whether realized before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits on appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it:

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

- (v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co operative Bank:

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing or the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- 3. The Central Government hereby also directs that during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank,—
 - (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Mumbai District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
 - (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Cc-operative Bank Ltd., or with may other bank for the purpose of making the payments aforesaid:

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank 1 td. or such other Bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amount are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;
- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise, charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent,—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Cooperative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 10(5)|93 Dev.] P. K. TEJYAN. Under Secy.